दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>आप.वि.वा. 2445/2021, आप.वि.आ. 16082/2021 (रोक) और</u>
<u>आप.वि.आ. 16083/2021 (छूट),</u>
<u>आप.वि.वा. 2446/2021, आप.वि.आ. 16084/2021 (रोक) और</u>
<u>आप.वि.आ. 16085/2021 (छूट) और</u>
<u>आप.वि.वा. 2438/2021 और आप.वि.आ. 16048/2021 (रोक)</u>

सुरक्षित : 10.12.2021
निर्णय की तिथि : 31.01.2022

<u>निम्न मामले में :-</u>

मैसर्स रायपति पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर

..... याचिकाकर्तागण

द्वारा: श्री ध्रुव द्विवेदी और श्री शेख बख्तियार, अधिवक्ता

बनाम

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी लिमिटेड (इरेडा)

..... प्रत्यर्थी

द्वारा:

मैसर्स रायपति पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर

..... याचिकाकर्तागण

द्वारा: श्री ध्रुव द्विवेदी और श्री शेख बख्तियार, अधिवक्ता

बनाम

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी लिमिटेड (इरेडा)

..... प्रत्यर्थी

द्वारा:

मैसर्स रायपति पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर

..... याचिकाकर्तागण

द्वारा: श्री ध्रुव द्विवेदी और श्री शेख बख्तियार, अधिवक्ता

बनाम

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी लिमिटेड (इरेडा)

..... प्रत्यर्थी

द्वारा:

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार ओहरी

निर्णय

मनोज कुमार ओहरी, न्या.

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें विद्वान महानगर दंडाधिकारी के समक्ष लंबित आपराधिक शिकायत संख्या 20581/2016, 15489/2016 और 941/2017 को रद्द करने की मांग की गई है। जबकि याचिकाकर्ता नंबर 1 आरोपी कंपनी है, याचिकाकर्ता नंबर 2 इसके प्रबंध निदेशक / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं।

2. उपरोक्त याचिकाएं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (इसके बाद, जिसे 'एनआई अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है) की धारा 138 के साथ

धारा 141/142 के तहत दायर विभिन्न शिकायतों से उत्पन्न होती हैं और इसमें समान पक्ष शामिल होते हैं। तदनुसार, याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए लिया जाता है और एक समान आदेश द्वारा निपटाया जाएगा।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आपराधिक शिकायतें याचिकाकर्ताओं के संबंध में सुनवाई योग्य नहीं हैं, क्योंकि संबंधित कानुनी डिमांड नोटिस एनआई अधिनियम के तहत निर्धारित 30 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद जारी किए गए थे। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त नोटिस अमान्य होने के कारण, धारा 138(ख) एनआई अधिनियम के आवश्यक तत्व संतुष्ट नहीं हैं और इस प्रकार, आक्षेपित आपराधिक शिकायतों को रद्द किया जाना चाहिए।

4. मैंने की गई प्रस्तुतियों को सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है।

5. मामले के अभिलेख को पढ़ने से पता चलेगा कि प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता एक कंपनी है जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उधार देने के व्यवसाय में है। ऋण सुविधा के लिए याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा संपर्क किए जाने के अनुसरण में, शिकायतकर्ता कंपनी और याचिकाकर्ता कंपनी के बीच एक लेनदेन किया गया था, जिसमें से याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता कंपनी के पक्ष में क्रमशः 31.03.2015, 30.09.2015 और 30.06.2016 को तीन चेक

जारी किए गए थे। तथापि, विचाराधीन चेक प्रस्तुतीकरण पर अस्वीकृत हो गए और उन्हें क्रमश: दिनांक 29.05.2015, 19.10.2015 और 21.07.2016 के रिटर्न मेमो के माध्यम से लौटा दिया गया, जिस पर लिखा था कि '*चेक कर्ता के साइन अलग-अलग हैं*' और '*कोई फंड नहीं है*'।

शिकायतकर्ता कंपनी को उक्त चेकों के संबंध में 19.06.2015, 29.10.2015 और 27.07.2016 को अपने बैंक से रिटर्न स्टेटमेंट प्राप्त हुए हैं, जो दर्शाता है कि इसका नकार दिया गया था। नतीजतन, इसने क्रमशः 07.07.2015, 28.11.2015 और 26.08.2016 को कानूनी डिमांड नोटिस पोस्ट किए, जिसमें याचिकाकर्ता कंपनी को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बकाया ऋण चुकाने के लिए कहा गया। जब वैधानिक अवधि के भीतर देय राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आक्षेपित आपराधिक शिकायतें दायर की गईं, जो ऊपर उल्लिखित क्रमशः आरोपी कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं।

उपर्युक्त शिकायतों का विवरण नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में दिया गया है: -

आपराधिक शिकायत सं.	चेक की तिथि	वापसी ज्ञापन की तिथि	रिटर्न स्टेटमेंट प्राप्त करने की तिथि	कानूनी नोटिस पोस्ट करने की तिथि
20581/2016	31.03.2015	29.05.2015	19.06.2015	07.07.2015
15489/2016	30.09.2015	19.10.2015	29.10.2015	28.11.2015
941/2017	30.06.2016	21.07.2016	27.07.2016	26.08.2016

6. आपराधिक शिकायतों में, यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता कंपनी ने दिनांक 07.12.2005 के ऋण समझौते के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनी को 2014.00 लाख रुपये की ऋण सुविधा को मंजूरी दी और वितरित किया था। अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए, याचिकाकर्ता कंपनी ने विभिन्न चेक जारी किए थे, जिनमें से 3 चेक, जैसा कि शिकायतों में उल्लेख किया गया है, अस्वीकृत हो गए और चेक नकारे जाने के तथ्य को उसके बैंक द्वारा शिकायतकर्ता कंपनी को उपर्युक्त रिटर्न स्टेटमेंट के माध्यम से सूचित किया गया था।

जहां तक याचिकाकर्ता नंबर 2 का संबंध है, यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि वह याचिकाकर्ता कंपनी के प्रबंध निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिन्होंने चेक पर हस्ताक्षर किए थे। आगे यह आरोप लगाया गया कि संबंधित समय में, याचिकाकर्ता नंबर 2 न केवल याचिकाकर्ता कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों और व्यवसाय के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था, बल्कि उसने

कंपनी की ओर से ऋण लेनदेन पर बातचीत भी की थी और ऋण के पुनर्भुगतान की गारंटी दी थी।

7. वर्तमान मामले में शामिल संक्षिप्त मुद्दा यह है कि शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा जारी कानूनी डिमांड नोटिस धारा 138(ख) एनआई अधिनियम के तहत निर्धारित तीस दिनों की सीमा अवधि के भीतर भेजे गए थे या नहीं।

8. वर्तमान मामले में शामिल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, पहले इसके तहत धारा 138 (ख) एनआई अधिनियम को उल्लिखित करना लाभदायक माना जाता है, जो निम्नानुसार है: -

> *"138. ... बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि-*
>
> *xxx*
>
> *(ख) आदाता या धारक चेक के नियत समय में, जैसा भी मामला हो, <u>उसके द्वारा तीस दिनों के भीतर बैंक से चेक की बिना भुगतान वापसी के बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद,</u> चेक के कर्ता को लिखित में नोटिस देकर उक्त धनराशि के भुगतान की मांग करता है; और"*
>
> *(जोर दिया गया)*

9. संक्षेप में, धारा 138 एनआई अधिनियम चेक के नकारे जाने से संबंधित अपराध के लिए दंड प्रदान करता है, जो उसके परंतुक में निर्धारित शर्तों के अधीन है। विशेष रूप से, परंतुक के खंड (ख) में यह निर्धारित किया गया है कि धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अपराध को स्थापित करने के लिए,

शिकायतकर्ता द्वारा यह सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अभियुक्त को एक कानूनी डिमांड नोटिस जारी किया जाना चाहिए था कि चेक भुगतान न होने के रूप में वापस कर दिया गया था।

10. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एन.आई. अधिनियम, एक दंड संविधि होने के नाते, सख्त रचना की मांग करता है और परिणामस्वरूप, एनआई अधिनियम के तहत किसी अभियुक्त को आपराधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार ठहराने से पहले, कथित रूप से किए गए अपराध के आवश्यक अवयवों को संतुष्ट करना आवश्यक है।

11. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियों के दौरान उठाया गया प्राथमिक मुद्दा यह है कि शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा चेक नकार दिए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, यानी रिटर्न मेमो की तारीख से, कानूनी डिमांड नोटिस जारी नहीं किए गए थे, और इस प्रकार शिकायतें सुनवाई योग्य नहीं हैं। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता कंपनी का कहना है कि उसे चेक नकारे जाने के बारे में तभी सूचित किया गया था जब उसके बैंक ने उपरोक्त रिटर्न स्टेटमेंट भेजे थे, और उसके बाद 30 दिनों के भीतर कानूनी डिमांड नोटिस जारी किए गए थे।

12. इसी तरह के तथ्यात्मक आव्यूह के तहत, मुनोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

<u>बनाम पट्टुकोला प्रॉपर्टीज लिमिटेड और एक अन्य</u> **(2001) 6 एससीसी 582** मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 138(ख) एनआई अधिनियम में निहित कानून की व्याख्या की है, जैसा कि यह 2002 में संशोधन से पहले था :-

> *"5. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने महानगर दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त साक्ष्यों का उल्लेख नहीं करके एक ठोस अनियमितता की। अधिनियम की धारा 138(ख) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि आदाता को चेक की वापसी के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के कर्ता को नोटिस देकर धनराशि के भुगतान की मांग करनी होगी। इसलिए पंद्रह दिनों को चेक के भुगतान न किए जाने के रूप में वापसी के बारे में सूचना प्राप्त होने से गिना जाना है। वर्तमान मामले में, यह शिकायतकर्ता का कहना है कि चेक 12 तारीख को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था; इसे 13 तारीख को बैंक को लौटा दिया गया और शिकायतकर्ता को 17 तारीख को ही सूचना दी गई, क्योंकि 14, 15 और 16 तारीख को पोंगल की छुट्टियां थीं। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि शिकायत में यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता को 13-1-1994 को अपने बैंकर से उक्त चेक की वापसी के संबंध में सूचना मिली थी। हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह एक स्पष्ट गलती है और उस गलती को समझाने के लिए अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया है। निर्विवाद रूप से, उन्होंने बताया कि तमिलनाडु राज्य में 14-1-1994 से 16-1-1994 तक पोंगल की छुट्टियां थीं और इसलिए, अपीलकर्ता को 17-1-1994 को अपने चेक के नकारे जाने के बारे में पता चला।*

13. एन. परमेश्वरन उन्नी बनाम जी. कन्नन और अन्य **(2017) 5 एससीसी 737** के रूप में प्रकाशित मामले में निर्णय पर भी ध्यान दिया जाता है, जहां धारा 138(ख) एनआई अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए, जैसा कि यह 2002 में संशोधन से पहले था, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार राय व्यक्त की है :-

> *"एनआई अधिनियम की धारा 138 को पढ़ने से संकेत मिलता है कि धारा 138 का उद्देश्य चेक के बेईमान कर्ताओं को रोकना और दंडित करना है जो अपनी देयता को टालते हैं और बचते हैं। जैसा कि परंतुक के खंड (ख) में बताया गया है, आदाता या चेक के धारक को नियत समय में नकारे जाने के बारे में बैंक से प्राप्त सूचना की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर चेक के कर्ता पर एक लिखित नोटिस तामील करना आवश्यक है।"*
>
> *(जोर दिया गया)*

14. इस बात की विवेचना करने के लिए कि शिकायतकर्ता द्वारा चेक बाउंस के संबंध में सूचना प्राप्त होने के दिन को धारा 138 (ख) एनआई अधिनियम के तहत परिसीमा अवधि की गणना में शामिल किया जाना है या नहीं, **(2014) 11 एससीसी 769** के रूप में प्रकाशित ईकॉन एंट्री लिमिटेड बनाम रोम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय को संदर्भित करना उचित समझा जाता है। जहां उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने एक संदर्भ का उत्तर देते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 138 एनआई अधिनियम में दो अलग-अलग शब्दों का उपयोग, यानी 'फ्रॉम' और 'ऑफ', अलग-अलग अर्थों का संकेत है और **(1999) 3 एससीसी 1** के रूप में प्रकाशित साकेत

इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड और **(1999) 4 एससीसी 567** के रूप में प्रकाशित एसआईएल इंपोर्ट, यूएसए बनाम एक्जिम एड्ज सिल्क एक्सपोर्टर्स, बंगलौर में लिए गए परस्पर विरोधी विचारों से उत्पन्न संघर्ष को निम्नलिखित शर्तों में हल किया :-

> *"26. हमने साकेत को बड़े पैमाने संदर्भित किया है। साकेत में इस न्यायालय का तर्क उपरोक्त अंग्रेजी निर्णयों और हरू दास गुप्ता में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर दिया गया है, जो इस सिद्धांत को उपयुक्त रूप से निर्धारित और स्पष्ट करता है कि जहां एक निश्चित तारीख से एक विशेष समय दिया जाता है जिसके भीतर एक कार्य किया जाना है, तारीख के दिन को बाहर रखा जाना है, यह इसे एसआईएल इंपोर्ट, यूएसए में इस न्यायालय के तर्क के विपरीत ठहराता है, जहां उक्त निर्णयों का कोई संदर्भ नहीं है।*
>
> *xxx*
>
> *28. हालांकि, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अलग-अलग स्थानों पर धारा 138 में "फ्रॉम" और "ऑफ" दो अलग-अलग शब्दों का उपयोग करना उक्त शब्दों द्वारा अलग-अलग अर्थों को व्यक्त करने के लिए विधायिका के इरादे को स्पष्ट करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एनआई अधिनियम की धारा 138(ग) और 142(ख) में आने वाले शब्द "ऑफ" की व्याख्या एनआई अधिनियम की धारा 138(क) में आने वाले "फ्रॉम" शब्द के विपरीत अलग-अलग तरीके से की जानी चाहिए। "फ्रॉम" शब्द को प्रश्नगत तारीख को बाहर रखे जाने के रूप में लिया जा सकता है और यह सामान्य खंड अधिनियम, 1897 द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, "ऑफ" शब्द अलग है*

और निर्धारित अवधि के शुरू होने के शुरुआती दिन को शामिल करने के रूप में इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। यह सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 द्वारा शासित नहीं है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, धारा 142(ख) के प्रयोजनों के लिए, जो यह निर्धारित करता है कि शिकायत उस तारीख के 30 दिनों के भीतर दायर की जानी है, जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, 30 दिनों की अवधि की गणना के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की प्रारंभिक तिथि को शामिल किया जाना चाहिए।

29. हम उनकी दलील से प्रभावित नहीं हैं।...

xxx

34. चूंकि परिसीमा अधिनियम को एनआई अधिनियम पर लागू नहीं माना जाता है, इसलिए तरुण प्रसाद चटर्जी, जहां परिसीमा अधिनियम को लागू नहीं माना गया था, के समानांतर हमारी राय है कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 की सहायता से वर्तमान मामले में यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एनआई अधिनियम की धारा 142(ख) के तहत निर्धारित एक महीने की अवधि की गणना करते समय, उस तारीख को छोड़कर अवधि की गणना की जानी चाहिए जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था। प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता से सहमत होना संभव नहीं है कि धारा 138 में अलग-अलग स्थानों पर दो अलग-अलग शब्दों "फ्रॉम" और "ऑफ" का उपयोग उक्त शब्दों द्वारा अलग-अलग अर्थों को व्यक्त करने के लिए विधायिका के इरादे को इंगित करता है।

xxx

39. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह कहना संभव नहीं है कि एनआई अधिनियम की धारा 138(ग) और 142(ख) में होने

वाले शब्द "ऑफ" की व्याख्या एनआई अधिनियम की धारा 138(क) में होने वाले "फ्रॉम" शब्द के विपरीत अलग-अलग की जानी चाहिए; और यह कि धारा 142(ख) के प्रयोजनों के लिए, जो यह निर्धारित करता है कि शिकायत उस तारीख के 30 दिनों के भीतर दर्ज की जानी है, जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, उसे 30 दिनों की अवधि की गणना के लिए शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि फॉलन में कहा गया है, किसी दिए गए मामले में "ऑफ", "फ्रॉम" और "आफ्टर" शब्दों का अर्थ वास्तव में एक ही बात हो सकता है। जैसा कि स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश, खंड 3, 1953 संस्करण, नोट (5) में कहा गया है, शब्द "ऑफ" कभी-कभी "आफ्टर" के बराबर होता है।

xxx

42. प्रासंगिक निर्णयों के आलोक में, इस मामले में शामिल कानून के प्रश्न पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने के बाद, हमारी राय है कि साकेत कानून का सही प्रस्ताव निर्धारित करता है। हम मानते हैं कि एक महीने की अवधि, जो एनआई अधिनियम की धारा 142(ख) के तहत निर्धारित है, की गणना करने के उद्देश्य से अवधि की गणना उस तारीख को छोड़कर की जानी चाहिए जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था। हम मानते हैं कि एसआईएल इंपोर्ट, यूएसए सही कानून निर्धारित नहीं करता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय का कोई भी निर्णय जो इस न्यायालय द्वारा साकेत में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण रखता है, जिसकी हमारे द्वारा पुष्टि की गई है, इस संदर्भ में शामिल प्रश्न पर सही कानून निर्धारित नहीं करता है। संदर्भ का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

(जोर दिया गया)

15. इकोन एंट्री (पूर्वोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण को उच्चतम न्यायालय द्वारा

दोहराया गया है और **(2014) 11 एससीसी 759** के रूप में प्रकाशित रमेश चंद्र अम्बालाल जोशी बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में लागू किया गया है।

16. हाल ही में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने **2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 236** के रूप में प्रकाशित सिमरनपाल सिंह सूरी बनाम राज्य और अन्य के मामले में, जिसमें परिसीमा के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई और धारा 138/142 एनआई अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए इकोन एंट्री (पूर्वोक्त) में निर्णय पर भरोसा किया।

17. इकोन एंट्री (पूर्वोक्त), जो तथापि धारा 138 (सी) और धारा 142(ख) एनआई अधिनियम के संबंध में प्रदान किया गया एक निर्णय है, को देखते हुए यह स्पष्ट है कि धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत उपयोग किए जाने वाले शब्द 'ऑफे' और 'फ्रॉम' का अर्थ अलग-अलग नहीं है। यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि धारा 138(ख) एनआई अधिनियम में 'ऑफ' शब्द के उपयोग का अर्थ यह नहीं है कि जिस दिन शिकायतकर्ता द्वारा बैंक से चेक के नकारे जाने के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे वैध कानूनी नोटिस जारी करने की परिसीमा अवधि की गणना करते समय शामिल किया जाना है।

जैसा कि ऊपर उल्लिखित न्यायिक आदेश से पता चलता है, कानूनी स्थिति यह है कि वैध कानूनी नोटिस जारी करने के लिए एनआई अधिनियम की धारा

138(ख) के तहत निर्धारित 30 दिनों की परिसीमा अवधि की गणना करते समय, जिस दिन शिकायतकर्ता को बैंक से सूचना प्राप्त होती है कि संबंधित चेक भुगतान के बिना वापस कर दिया गया है, उसे दिन को बाहर रखा जाना चाहिए।

18. वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून को लागू करते हुए, यह ध्यान दिया जाता है कि याचिकाकर्ता कानून में निर्धारित 30 दिनों की अवधि की गणना करने के लिए रिटर्न मेमो की तारीखों, यानी, विचाराधीन चेक की वापसी की तारीखों पर भरोसा करता है और तर्क देता है कि कानूनी डिमांड नोटिस समय पर जारी नहीं किए गए थे। इसके विपरीत, यह प्रस्तुत करने के लिए कि कानूनी डिमांड नोटिस वैधानिक अवधि के भीतर जारी किए गए थे, शिकायतकर्ता अपने बैंक से रिटर्न स्टेटमेंट की प्राप्ति की तारीखों पर निर्भर करता है, यानी, जिन तारीखों पर विचाराधीन चेक के नकारे जाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी।

19. मुनोथ निवेश (पूर्वोक्त) में निर्णय, जहां उच्चतम न्यायालय ने परिसीमा के मुद्दे पर निर्णय करने के लिए विचाराधीन चेक की वापसी की तारीख के बजाय, शिकायतकर्ता द्वारा ऋण सलाह प्राप्त करने की तारीख को ध्यान में रखा, इकोन एंट्री (पूर्वोक्त) में निर्णय का अनुपात, और वर्तमान मामले में अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर यह दर्शाने के लिए विचार करते हुए कि विचाराधीन चेकों के नकारे जाने के बारे में सूचना शिकायतकर्ता कंपनी के ध्यान में रिटर्न स्टेटमेंट के माध्यम से आई थी, इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि

शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा कानूनी नोटिस अपने बैंक से संबंधित चेकों के नकारे जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पोस्ट किए गए थे और ये समय-बाधित नहीं थे। याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क इस न्यायालय को प्रभावी नहीं लगते हैं और तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं। हालांकि, साथ ही, यह बचाव भी कि शिकायतकर्ता कंपनी को अपने बैंक से रिटर्न स्टेटमेंट प्राप्त करने से पहले चेक के नकारे जाने की जानकारी प्राप्त हो गई थी, याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, लेकिन यह तथ्य का प्रश्न होने के नाते विचारण का विषय होगा।

20. तदनुसार, याचिकाओं को खारिज किया जाता है। विविध आवेदनों को असफल के रूप में निपटाया जाता है।

(मनोज कुमार ओहरी)
न्यायाधीश

31 जनवरी, 2022/एनए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*